एस. एस. संधावालिया सी. जे. और आर. एन. मित्तल से पहले जे.

हरियाणा राज्य और अन्य, अपीलकर्ता /

बनाम

हाकम सिंह और अन्य, *उत्तरदाता।*

***लेटर्स पेटेंट अपील नं.* 1974 *का* 345।**

15 जनवरी, 1979।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम(1894 का 1) - धारा *4 और* 6 *और भाग VII - 'सार्वजनिक उद्देश्य' - का अर्थ - आवासीय और* वाणिज्यिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि - सरकार द्वारा भुगतान किए गए अधिग्रहण के लिए मुआवजा - एकीकृत विकास के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी *को अधिग्रहित भूमि - लाभ के विचार के लिए कंपनी द्वारा किया गया विकास - इस तरह का अधिग्रहण - क्या शक्ति का एक रंगीन प्रयोग - प्रावधान भाग VII - क्या पालन किया जाना आवश्यक है।*

(सात) ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 123.

हरियाणा राज्य और अन्य *बनाम*हाकम सिंह और अन्य *
(आर एन ^ मित्तल, जे।

*और रूप*भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में परिभाषित 'सार्वजनिक उद्देश्य' शब्द एक समावेशी परिभाषा है और इस प्रकार उक्त शब्द के दायरे को निर्धारित करने के लिए बहुत सहायता नहीं है। उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग सामान्य अर्थों में किया गया है। इसमें एक उद्देश्य शामिल है जिसमें व्यक्तियों के विशेष हित के विपरीत समुदाय का सामान्य हित सीधे संबंधित है। इसमें उस उद्देश्य को भी शामिल किया जाएगा जिसमें समुदाय का एक अंश रुचि रखता है। सार्वजनिक उद्देश्य इलाकों में समय और प्रचलित परिस्थितियों के साथ भिन्न होता है। इसलिए, समुदाय के लाभ के लिए आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों को विकसित करने वाली भूमि का अधिग्रहण एक सार्वजनिक उद्देश्य है। (पैरा 6)।

यह माना गया है कि अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि यदि राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इसका उपयोग राज्य द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। अधिग्रहण के लिए कानून की आवश्यकता यह है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और दिए जाने वाले मुआवजे का भुगतान पूरी तरह से या आंशिक रूप से सार्वजनिक राजस्व या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित कुछ निधियों से किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि पूरे मुआवजे का भुगतान राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन इसका भुगतान आंशिक रूप से राज्य द्वारा और आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। तथ्य यह है कि राज्य का योगदान >नाममात्र है, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि लेनदेन एक रंगीन लेनदेन है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को यह तय करने के लिए जाना होगा कि लेनदेन रंगीन है या नहीं। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी निजी एजेंसी के कहने पर अधिग्रहण को रोकता है जब तक कि अधिग्रहण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य है। यदि अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाता है, तो राज्य सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करने के बाद इसे एक कंपनी को सौंप सकती है जो सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करना है और भूमि के अधिग्रहण को शक्ति का एक रंगीन प्रयोग नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा, 6)।

संधावालिया, सीजे के अनुसार, यह निर्विवाद है कि पूरी तरह से नए या विकासशील शहरों में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए शहरी क्षेत्रों का विनियमित विकास एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है और इसलिए स्पष्ट रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के दायरे में आएगा। यह अपरिहार्य और शायद वांछनीय भी प्रतीत होता है कि सभी शहरों में समन्वित शहरीकरण का पूरा भार अपने ऊपर लेने में राज्य की अक्षमता के मामले में या अन्यथा अच्छे कारणों से, निजी उद्यम को न केवल प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, जब तक कि भूमि के शहरी विकास का व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य स्पष्ट और अस्पष्ट न हो। यह उम्मीद करना कि कोई भी निजी संगठन, शहरी विकास का भारी बोझ केवल परोपकारी विचारों के लिए उठाएगा और लाभ या लाभ के किसी भी उद्देश्य से रहित होगा।

बहुत यूटोपियन एक आदर्श बनें। एक बार विनियमित विकास का व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य स्पष्ट हो जाने के बाद, लाभ के विचार के लिए भी इस तरह के कार्य को एक निजी निकाय को सौंपना किसी भी तरह से उस बड़े सार्वजनिक उद्देश्य से अलग नहीं होगा या इसे रंगीन नहीं माना जाएगा। विनियमित शहरीकरण के उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निजी संगठन को अधिग्रहण के माध्यम से कुछ सहायता प्रदान करना शक्ति का एक रंगीन अभ्यास नहीं होगा। (पैरा 15, 18 और 19) '

यह माना गया कि अधिनियम की धारा 4 के तहत एक उपयुक्त सरकार किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक होने पर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है। यदि भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया है और मुआवजे का पूरा या कुछ हिस्सा सरकार द्वारा सार्वजनिक राजस्व में से भुगतान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को अधिनियम के भाग VII के प्रावधानों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 13)

माननीय न् यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन द्वारा दिनांक 6 मई, 1974 को सिविल रिट सं 2004 में पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट एक् ट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील। 1973 का 1666 ।

अपीलकर्ताओं की ओर से *एस. सी. मोहंता, ए. जी. हरियाणा।*

एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता और आर. सी. सेतिया, अधिवक्ता।

सी. डी. दीवान, एडवोकेट और एन. सी. जैन, एडवोकेट, उत्तरदाताओं *के लिए।*

निर्णय

राजेंद्र नाथ मित्तल, जे।

(एक) यह निर्णय 1974 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 342 से 345 और 386 से 389 का निपटारा करेगा, जिसमें कानून के समान प्रश्न शामिल हैं। फैसले में तथ्य 1974 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 345 से दिए जा रहे हैं।

(दो) प्रतिवादी नंबर 1 हुकम सिंह गुड़गांव जिले की तहसील बल्लभगढ़ के गांव सीही की राजस्व संपदा के भीतर स्थित लगभग 57 बीघा भूमि के मालिक हैं, जिसका उपयोग वह कृषि उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। डीएलएफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) प्रतिवादी नंबर 2 ने फरीदाबाद के सेक्टर 10 और 11 को विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उक्त जमीन सेक्टर 10 के भीतर आती है। यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी के निदेशक प्रभावशाली लोग हैं और उन्होंने सरकार पर धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने का दबाव डाला।

5si

प्रतिवादी नंबर 1 की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) जिसे बाद में उनके अभ्यावेदन पर वापस ले लिया गया था। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई जो 3 अक्टूबर, 1972 को प्रकाशित हुई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने फिर से अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज कीं और राज्य ने 22 फरवरी, 1973 को अधिसूचना वापस ले ली। इसके बाद, एक और अधिसूचना दिनांकित हुई। 23 फरवरी, 1973 को राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किया गया था जो उसी दिन प्रकाशित हुआ था। प्रतिवादी नंबर 1 ने धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज कीं। यह आरोप लगाया गया है कि बिना किसी जांच के अपीलकर्ता संख्या 3 ने सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद 3 मई, 1973 को धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य बातों के साथ-साथ अधिसूचना की वैधता और औचित्य को इस आधार पर चुनौती दी कि यह *राज्य सरकार द्वारा अधिकार क्षेत्र का बेरंग प्रयोग था, कि भूमि का अधिग्रहण अधिनियम के भाग VII के तहत किया जाना चाहिए था क्योंकि यह कंपनी के उद्देश्य के लिए किया जा रहा था और अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों का उचित निपटान नहीं किया गया था।*

(तीन) विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधिसूचनाएं राज्य सरकार द्वारा अधिकार क्षेत्र के रंगीन प्रयोग के तहत जारी की गई थीं। उन्होंने अन्य दो बिंदुओं पर निर्णय करना इस कारण से आवश्यक नहीं समझा कि उनके द्वारा रिट की अनुमति दी जा रही थी। उक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ दो अपील दायर की गई हैं, एक राज्य सरकार आदि प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 (1974 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 345) और दूसरी कंपनी (1974 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 387) द्वारा। अन्य तीन रिट याचिकाएं कुछ अन्य भूस्वामियों द्वारा इसी आधार पर दायर की गई थीं। उन रिट याचिकाओं को भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। प्रत्येक मामले में, दो अपील दायर की गई हैं, एक राज्य और आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा और दूसरी कंपनी द्वारा। इस प्रकार सभी आठ अपीलें हैं।

(चार) निर्धारण के लिए पहला सवाल यह उठता है कि क्या राज्य ने अपने अधिकार क्षेत्र के बेरंग प्रयोग के तहत अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं जारी की हैं। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि सेक्टर 10 और 11 को आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। लागू की गई अधिसूचनाओं में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए थी, अर्थात् आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास के लिए। यह अच्छी तरह से तय है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा, कि भूमि की आवश्यकता है

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, उक्त तथ्य को साबित करने के लिए निर्णायक सबूत है। उपरोक्त सिद्धांत का केवल एक अपवाद है। यह है कि यदि शक्ति का रंगीन प्रयोग किया जाता है, तो घोषणा चुनौती के लिए खुली होगी। शक्ति के रंगीन प्रयोग शब्द की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने *सोमवंती* बनाम केरल *मामले में की है। पंजाब राज्य* (1) निम्नानुसार है:

> "यदि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जिस बात से संतुष्ट है वह सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक निजी उद्देश्य है या कोई उद्देश्य नहीं है, तो सरकार की कार्रवाई रंगीन होगी क्योंकि यह अधिनियम द्वारा उसे दी गई शक्ति से संबंधित नहीं है। " '

तो मुख्य प्रश्न जिसके लिए निर्णय की आवश्यकता है, वह यह है कि 'सार्वजनिक उद्देश्य' क्या है? अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क यह है कि यदि आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता है तो यह एक सार्वजनिक उद्देश्य है, भले ही विकास एक कंपनी द्वारा किया जाना है। दूसरी ओर प्रतिवादियों के विद्वान वकील का तर्क यह है कि यदि भूमि को राज्य द्वारा ही विकसित किया जाना है, तभी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण पर विचार किया जा सकता है। उनके अनुसार वर्तमान मामले में अधिग्रहण का उद्देश्य कंपनी को लाभ कमाने के लिए भूमि देना है और इसे सार्वजनिक उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है।

(पाँच) Theuterm)1 सार्वजनिक [उद्देश्य है; अधिनियम में निम्नलिखित परिभाषित किए गए हैं
-

> '"सार्वजनिक उद्देश्य' शब्द में जिलों में ग्राम-स्थलों का प्रावधान शामिल है, जिसमें (उपयुक्त सरकार) ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया होगा कि सरकार के लिए ऐसा प्रावधान करना प्रथागत है।

यह एक समावेशी परिभाषा होने के नाते 'सार्वजनिक उद्देश्य' शब्द के दायरे को निर्धारित करने के लिए बहुत सहायता नहीं है। विभिन्न मामलों में इसकी न्यायिक व्याख्या भी की गई है। उनमें से कुछ को संदर्भित करना उपयोगी होगा। *हमावी प्रमजी पेटिट* वी। *राज्य सचिव*(2) ने न्यायिक समिति के समक्ष इसी तरह का एक मामला उठाया।

(एक) एआईआर 1963 एस.सी.
(दो) एआईआर 1914 प्रिवी काउंसिल 20.

हरियाणा राज्य और अन्य *बनाम* हाकम सिंह
और अन्य *

उस मामले में, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक पट्टा इस शर्त के साथ दिया गया था कि वह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि को फिर से शुरू कर सकती है। सरकार के कर्मचारियों के आवास के उद्देश्य से भवनों का निर्माण करने के लिए पट्टे को बाद में फिर से शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। एक तर्क यह दिया गया था कि पट्टे को बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए नहीं बल्कि सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने के लिए फिर से शुरू किया जा रहा है और इसे सार्वजनिक उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है। न्यायिक समिति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी, जिसमें बैचलर, जे ने इस शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया: –

"सामान्य परिभाषाएं हैं, मुझे लगता है कि जहां परिहार संभव है वहां टाला जाना चाहिए और मैं पट्टे में "सार्वजनिक उद्देश्य" वाक्यांश की सीमा को सटीक रूप से परिभाषित करने का कोई प्रयास नहीं करता हूं; यह कहने के लिए पर्याप्त है कि, मेरी राय में वाक्यांश, जो भी इसका मतलब हो सकता है, में एक उद्देश्य शामिल होना चाहिए, जो एक उद्देश्य या उद्देश्य है, जिसमें समुदाय का सामान्य हित, व्यक्तियों के विशेष हित के विपरीत, सीधे और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। इस तर्क को खारिज करते हुए कि यदि भूमि बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं थी, तो यह नहीं माना जा सकता कि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य था, प्रिवी काउंसिल ने कहा:

"ऐसा होने के नाते, जो कुछ भी बचा है वह यह निर्धारित करना है कि क्या यहां उद्देश्य एक उद्देश्य है जिसमें समुदाय के सामान्य हित से संबंधित है। *प्रथम दृष्टया* सरकार इसके लिए अच्छी न्यायाधीश है। वे पूर्ण न्यायाधीश नहीं हैं। वे यह नहीं कह सकते कि 'सिक वोलो सिक जेबो' लेकिन कम से कम एक अदालत उन्हें आसानी से गलत नहीं ठहराएगी। लेकिन यहां उन्हें गलत मानने से दूर, भारतीय जीवन की स्थितियों से भली-भांति परिचित सभी विद्वान न्यायाधीश कहते हैं कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि यह योजना ऐसी है जो सरकार को अपने सेवकों की दक्षता बनाए रखने में मदद करके सार्वजनिक लाभ पहुंचाएगी। इस तरह के निष्कर्ष से उनके प्रभुत्व में अंतर होने की गति धीमी होगी, और अपने स्वयं के बयान पर यह उनके फैसले की सराहना करता है।

उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ एक ऐसा उद्देश्य था जिसमें जनता का सामान्य हित इसके खिलाफ था

व्यक्तियों के विशेष हित सीधे संबंधित हैं। बॉम्बे *राज्य बनाम भांजी मुंजी*(3) मामले में, 1948 के बॉम्बे भूमि अधिग्रहण अधिनियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसमें स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताया गया था कि सरकार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। बोस, जे. पीठ की ओर से बोलते हुए इस प्रकार बोले:

"उस समय बॉम्बे में आवास की स्थिति गंभीर थी, मुख्य रूप से शरणार्थियों की आमद के कारण। सार्वजनिक शालीनता, सार्वजनिक नैतिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अराजकता और अपराध के प्रलोभन के सवाल, जो इस तरह की स्थिति अपनी ट्रेन में लाती है, एक बार फिर उठे; और सार्वजनिक विवेक सादे मानवता के आधार पर जागृत किया गया था।

उन्मादी जमींदारों के आकार में मालिकों की एक दौड़, जो उन लोगों के दुख पर पनपती थी, जिन्हें अपने सिर पर कोई सभ्य छत नहीं मिल सकती थी, अस्तित्व में आया। यहां तक कि प्रशासन की दक्षता भी खतरे में पड़ गई थी क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को उचित आवास नहीं मिल रहा था। बुराई *से निपटने के लिए* हल्के प्रयास अप्रभावी साबित हुए। इसलिए सरकार के लिए और कठोर कदम उठाना आवश्यक था और ऐसा करके उन्होंने जनता के हित के लिए कार्य किया। नतीजतन एक स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य और एक निस्संदेह सार्वजनिक लाभ था।

यह प्रश्न कई अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष दोहराया गया लेकिन मैं उनमें से तीन अर्थात् *बाबू बरक्या ठाकुर* बनाम *अन्य मामलों का उल्लेख करूंगा। बॉम्बे राज्य* (अब महाराष्ट्र) *और अन्य* (4), *सोमवंती* वी। *पंजाब राज्य* (5), और *रतिलाल* वी। *गुजरात राज्य* (6)। *बाबू बरक्या ठाकुर के मामले (सुप्रा) में, सिन्हा, सीजे ने* भांजी मुंजी के मामले *(सुप्रा) में फैसले का उल्लेख करने के बाद अदालत के लिए बोलते हुए* कहा कि अपने घरों से दूर बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देने वाली औद्योगिक चिंता में, यह एक सामाजिक आवश्यकता है कि ऐसे श्रमिकों के लिए उचित आवास उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक समुदाय के एक बड़े वर्ग का संबंध है, इसका कल्याण सार्वजनिक चिंता का विषय है। सोमवंती के मामले (सुप्रा) में यह माना गया था कि विशेष रूप से 'सार्वजनिक उद्देश्य' शब्द में एक उद्देश्य शामिल होगा जिसके लिए व्यक्तियों का सामान्य हित सीधे और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है।

(तीन) एआईआर 1955 एस.सी.
(चार) एआईआर 1960 एस.सी.
(पाँच) एआईआर 1963 एस.सी.
(छः) एआईआर 1970 एस.सी.

इसी तरह, हेगड़े, जे। *रतिलाल के मामले* (सुप्रा) में फैसला सुनाया कि सीमित संख्या में व्यक्तियों के लिए एक आवास योजना एक सार्वजनिक उद्देश्य है।

(छः) उपरोक्त चर्चा से, यह उभरता है कि अभिव्यक्ति सार्वजनिक उद्देश्य का उपयोग सामान्य अर्थों में किया गया है। इसमें एक उद्देश्य शामिल है जिसमें व्यक्तियों के विशेष हित के विपरीत समुदाय का सामान्य हित सीधे संबंधित है। इसमें उस उद्देश्य को भी शामिल किया जाएगा जिसमें समुदाय का एक अंश रुचि रखता है। बस इतना आवश्यक है कि यह समाज के सामान्य हितों की सेवा करेगा। यह अच्छी तरह से तय है कि सार्वजनिक उद्देश्य इलाकों में समय और प्रचलित परिस्थितियों के साथ भिन्न होता है (देखें *अर्नोल्ड रॉड्रिक्स* वी। *महाराष्ट्र राज्य* (7)। इसलिए, आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों को विकसित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है: तर्क का दूसरा हिस्सा यह है कि क्या किसी कंपनी द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए इसके विकास के लिए राज्य द्वारा भूमि का अधिग्रहण भी एक सार्वजनिक उद्देश्य का गठन करेगा। अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि यदि राज्य द्वारा सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इसका उपयोग राज्य द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। अधिग्रहण के लिए कानून की आवश्यकता यह है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता होती है और प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति का भुगतान पूरी तरह से या आंशिक रूप से सार्वजनिक राजस्व या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित कुछ निधियों से किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि पूरे मुआवजे का भुगतान राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन इसका भुगतान आंशिक रूप से राज्य द्वारा और आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। तथ्य यह है कि राज्य का योगदान नाममात्र है, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि लेनदेन एक रंगीन लेनदेन है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को यह तय करने के लिए जाना होगा कि लेनदेन रंगीन है या नहीं। यह मामला *एकीकृत नहीं है*, बल्कि न्यायालयों द्वारा ध्यान दिया गया है। *सोमवंती के मामले*(सुप्रा) में, पंजाब राज्य ने एक सार्वजनिक कंपनी के प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया, जिसे प्रशीतन, कंप्रेसर और सहायक उपकरणों की विभिन्न श्रेणियों के निर्माण के लिए एक कारखाना शुरू करना था। राज्य ने भूमि के कुल चूहों के लिए 100 रुपये की राशि का योगदान दिया, जिसकी कीमत 4,50,000 रुपये थी। यह माना गया कि धारा 6 के तहत अधिसूचना को इस तथ्य के बावजूद शक्ति के एक रंगीन प्रयोग के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि राज्य द्वारा योगदान की गई राशि के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं था *अर्नोद रॉड्रिक्स के मामले*(सुप्रा) में सरकार ने औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र में इसके उपयोग के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को सौंपने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया।

(सात) एआईआर 1966 एस.सी. 1788.

कार्य-क्षेत्र। एक तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार एक व्यक्ति से संपत्ति अर्जित करने और दूसरे को देने की हकदार नहीं है। इसे सीकरी, जे. ने न्यायालय के लिए बोलते हुए निम्नानुसार देखा:

> "उद्देश्य अर्थात "औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के रूप में भूमि का विकास और उपयोग" भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भीतर एक सार्वजनिक उद्देश्य है जैसा कि यह बॉम्बे विधानमंडल (एस) एआईआर 1955 एससी 41 (45) द्वारा किए गए संशोधन से पहले खड़ा था।
>
> 'सार्वजनिक उद्देश्य' समय और इलाकों में प्रचलित स्थितियों के साथ बदलता रहता है, और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में, स्थितियां ऐसी हैं कि यह अनिवार्य है कि राज्य को आवासीय और औद्योगिक स्थलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो वह कर सकता है। यह सच है कि ये आवासीय और औद्योगिक स्थल अंततः जनता के सदस्यों को आवंटित किए जाएंगे और उन्हें व्यक्तिगत लाभ मिलेगा, लेकिन यह सामान्य समुदाय के हित में है कि जनता के इन सदस्यों को कारखानों को स्थापित करने के लिए साइटें होनी चाहिए। आक्षेपित अधिसूचनाओं को जारी करने में मुख्य विचार जनता के सदस्यों के निजी आराम या लाभ के बारे में नहीं बल्कि आम जनता की भलाई के बारे में सोचना था। किसी भी दर पर जहां समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग चिंतित है, उसका कल्याण सार्वजनिक चिंता का विषय है और जब अधिसूचनाओं ने समुदाय के इस वर्ग के कल्याण को बढ़ाने के लिए काम किया है, तो यह सार्वजनिक उद्देश्य है और अधिसूचनाएं वैध हैं और इस आधार पर लागू नहीं की जा सकती हैं कि वे किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जारी नहीं किए गए थे।

इस संबंध में रतिलाल के मामले (सुप्रा) का *भी उल्लेख करना फायदेमंद होगा* , जिसमें एक पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा तैयार आवास योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। एक तर्क यह था कि चूंकि भूमि का अधिग्रहण एक कंपनी के लिए किया जा रहा था, इसलिए अधिनियम के भाग VU में धारा 40 से 42 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए था जो कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित हैं। इस तर्क को खारिज कर दिया गया और यह देखा गया कि यह नहीं माना जा सकता है कि सीमित संख्या में व्यक्तियों के लिए आवास योजना को सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसी तरह *जेज राम* वी में। *हरियाणा राज्य* (8), राज्य सरकार द्वारा किसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था?

एक कंपनी का लाभ जिसे चाइना-वेयर ग्लेज़्ड टाइल्स आदि के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करना था। उस मामले में भी सरकार ने 100/- रुपये की राशि का योगदान दिया। भूमि के मालिकों की ओर से एक तर्क दिया गया था कि सरकार को अधिनियम के भाग VII के प्रावधानों का सहारा लेना चाहिए था क्योंकि कंपनी के उद्देश्य को सार्वजनिक उद्देश्य नहीं माना जा सकता था। विवाद को स्वीकार नहीं किया गया और अधिग्रहण को बरकरार रखा गया। अपीलकर्ताओं के वकील ने ए. *एन. नाथ* बनाम *भारत का भी हवाला दिया। डब्ल्यू बी.* राज्य (9) उस मामले में संस्थान के सुधार के लिए एक निजी महिला कॉलेज के कॉलेज अधिकारियों के कहने पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी। इस बात पर आपत्ति उठाई गई थी कि राज्य सरकार निजी कॉलेज के प्रयोजनों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। एक खंडपीठ द्वारा यह माना गया था कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी निजी एजेंसी के कहने पर अधिग्रहण को रोकता है जब तक कि अधिग्रहण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य था। यह भी कहा गया कि अधिग्रहण एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था क्योंकि बड़ी संख्या में महिला छात्रों को जीवन के लिए खुद को तैयार करने के लिए उचित शिक्षा सुविधाएं दी जाएंगी। उपर्युक्त मामलों से, यह स्पष्ट है कि यदि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो राज्य सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करने के बाद इसे एक कंपनी को सौंप सकती है जो सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करना है।

(सात) अब मैं वर्तमान मामले के तथ्यों का उल्लेख करता हूं। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, कंपनी फरीदाबाद में सेक्टर 10 और 11 विकसित कर रही है जो एक विकासशील शहर है और इसमें बड़ी संख्या में उद्योग शामिल हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां कई नए उद्योग आ रहे हैं। उद्योगों की वृद्धि के साथ शहर की आबादी भी बढ़ रही है। परिस्थितियों में, शहर के निवासियों को आवासीय और वाणिज्यिक आवास प्रदान करना आवश्यक है। कंपनी के पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन उस क्षेत्र में कुछ पॉकेट निजी उत्तरदाताओं के हैं। क्षेत्रों को ठीक से विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी द्वारा अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ पॉकेट विकसित किए जाने चाहिए अन्यथा विकास एक समान नहीं हो सकता है। यदि व्यक्तिगत मालिकों को भूमि के छोटे टुकड़े विकसित करने की अनुमति दी जाती है, तो विकास को एकीकृत नहीं किया जा सकता है और इससे जर्जर रूप देने की संभावना है। ऐसे परिणामों से बचने के लिए, क्षेत्रों का एकीकृत विकास ही एकमात्र समाधान है।

(आठ) प्रतिवादियों के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि गांव सीही उस क्षेत्र के भीतर स्थित था जहां

(नौ) 1977 कलकत्ता साप्ताहिक नोट्स 647.

पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1983 (इसके बाद नियंत्रित अधिनियम के रूप में संदर्भित) लागू था और कोई भी निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूखंड विकसित नहीं कर सकता था। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि कंपनी ने क्षेत्र के विकास के लिए निदेशक को योजनाएं प्रस्तुत कीं, जिसमें उसने निजी मालिकों से संबंधित भूमि को अपने स्वयं के रूप में दिखाया। इसके बाद निदेशक ने कंपनी को निजी मालिकों की भूमि का अधिग्रहण करने का सुझाव दिया। हालांकि, कंपनी ने इस आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया कि निजी मालिक अत्यधिक कीमत की मांग कर रहे थे और सरकार से भूमि का अधिग्रहण करने और इसे कंपनी को सौंपने का अनुरोध किया। कंपनी के निदेशकों, जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, के कहने पर सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया और बदले में दूसरे स्थान पर 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्र प्राप्त करने पर इसे कंपनी को हस्तांतरित करने पर सहमत हुई। हालांकि, राज्य ने विकसित भूखंडों के बिक्री मूल्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, इस तथ्य के बावजूद कि राज्य ने कंपनी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था। वकील का कहना है कि कंपनी अपने द्वारा तय की गई कीमतों पर भूखंडों को बेचकर भारी लाभ कमाएगी। श्री सिब्बल ने जोरदार तर्क दिया कि वास्तव में भूमि का अधिग्रहण जनता के उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि कंपनी के लाभ के लिए किया गया है। उनके अनुसार, ये तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अधिग्रहण राज्य द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके किया गया है।

(नौ) मैंने 1 से 3 विद्वान सलाह पर विचार किया है, लेकिन इसे स्वीकार करने में असमर्थता के लिए खेद है। राज्य द्वारा सेक्टर 10 और 11 के एकीकृत और कॉम्पैक्ट विकास के हित में भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया गया है। इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है, अगर निजी मालिकों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया होता, तो सेक्टर 10 और 11 का विकास एक समान नहीं हो सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि राज्य निजी मालिकों की भूमि कंपनी को सौंपने के लिए सहमत हो गया है, लेकिन इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि लेनदेन रंगीन है। *सोमवंती और जागे राम के मामले* (सुप्रा) में भूमि का अधिग्रहण कंपनियों के उद्देश्य के लिए किया गया था और अधिग्रहण शुल्क के लिए राज्य द्वारा एक छोटा योगदान दिया गया था। दोनों मामलों में अधिग्रहण को अच्छा माना गया था। वर्तमान मामले में आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूखंडों के विकास के लिए सार्वजनिक निधि से मुआवजे का भुगतान करके भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश के नागरिकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराना एक सार्वजनिक उद्देश्य है। राज्य कल्याणकारी गतिविधियों के बोझ से दबा हुआ है और यह इसके लिए संभव नहीं हो सकता है।

ऐसी सभी गतिविधियों को करने के लिए धन की कमी या अन्यथा। यदि यह उचित समझता है तो यह कुछ गतिविधियों को निजी कंपनियों को सौंप सकता है। उस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह परोक्ष उद्देश्य से किया गया है क्योंकि निजी कंपनियां सौदे से कुछ लाभ कमाएंगी। यह स्वाभाविक है कि यदि कोई कंपनी कोई काम करती है, तो यह कुछ लाभ कमाने के लिए किया जाता है। वर्तमान मामले में निजी मालिक जमीन की अत्यधिक कीमत की मांग कर रहे थे। उस स्थिति में राज्य ने सार्वजनिक धन से भूमि का अधिग्रहण करने और इसे कंपनी को सौंपने का विकल्प चुना। तथ्य यह है कि राज्य द्वारा किसी अन्य स्थान पर अधिग्रहित भूमि के बदले में 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्र लिया गया है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मेरा स्पष्ट रूप से विचार है कि राज्य द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं है।

(दस) निजी प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाना चाहिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज की ं और उसे कोई सुनवाई नहीं दी गई और उसके द्वारा मामले को ठीक से निपटाया नहीं गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिसूचनाएं इस छोटे से आधार पर रद्द की जा सकती हैं।

(ग्यारह) मैं श्री सिब्बल के तर्क से सहमत नहीं हूं। लिखित बयान में यह विशेष रूप से कहा गया है कि धारा 5 ए के तहत दायर आपत्तियों के संबंध में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा प्रतिवादी को सुना गया था और उसके बाद रिपोर्ट सरकार के निर्णय के लिए प्रस्तुत की गई थी। धारा 5ए में मालिक के भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से सुनवाई पर विचार किया गया है। इस मामले में, रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि धारा 5 ए के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया था। इसलिए, मैं विद्वान वकील की दलील को अस्वीकार करता हूं।

(बारह) श्री सिब्बल ने तब जोरदार तर्क दिया था कि भूमि का अधिग्रहण एक कंपनी के लिए किया जा रहा था और राज्य सरकार को भाग VII के प्रावधानों का सहारा लेना चाहिए था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि इस मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाया गया था, लेकिन उनके द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है।

(तेरह) मुझे इसमें कोई दम भी नजर नहीं आता। धारा 4 के तहत उपयुक्त सरकार को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जब भी भूमि की आवश्यकता होने की संभावना हो, अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया है। वर्तमान मामले में

भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया है और पूरे मुआवजे का भुगतान सरकार द्वारा सार्वजनिक राजस्व से किया गया था। ऐसी स्थिति में सरकार को अधिनियम के भाग VII के उपबंधों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा *जागे राम के मामले*(सुप्रा) में तय किया गया है। उस मामले में भी मालिकों की ओर से एक तर्क दिया गया था कि अधिग्रहण सरकार द्वारा भाग VII के तहत किया जाना चाहिए था क्योंकि कंपनी के उद्देश्य के लिए भूमि ^ अधिग्रहित की जा रही थी। यह हेगड़े, जे द्वारा निम्नानुसार देखा गया था:

> "हमें बार में सूचित किया गया था कि राज्य सरकार ने भूमि की लागत के लिए 100 रुपये की राशि का योगदान दिया था, जो तथ्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पुरस्कार में भी उल्लिखित है। ऐसा होने पर सरकार के लिए अधिनियम के भाग VII के तहत अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ना आवश्यक नहीं था (देखें सोमवंती का मामला (सुप्रा)।

उपरोक्त टिप्पणियां इस मामले पर पूरी तरह से लागू होती हैं। इसलिए, मैं विद्वान वकील के इस तर्क को भी अस्वीकार करता हूं।

(चौदह) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

(पंद्रह) पहले से ही अधिक आबादी वाले देश में गांवों से कस्बों की ओर लोगों का अपरिहार्य पलायन जैसे-जैसे गति पकड़ता जा रहा है, त्वरित शहरीकरण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और वास्तव में, कभी-कभी समाधान की अवहेलना करती दिखाई देती हैं। इसलिए, यह निर्विवाद है कि पूरी तरह से नए या विकासशील शहरों में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए शहरी क्षेत्रों का विनियमित विकास एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है और इसलिए, स्पष्ट रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के दायरे में आएगा। यह स्थिति, वास्तव में, सभी हाथों पर स्वीकार की जाती है। . , • *टन*

(सोलह) एक बार ऐसा होने के बाद, यह सवाल उठता है कि शहरी क्षेत्रों के समन्वित विकास का काम किसे सौंपा जाए। पूर्णता के एक सलाहकार के रूप में यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि राज्य को स्वयं इस महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन क्या होगा यदि राज्य के पास शहरी क्षेत्र को निर्धारित करने और अधिग्रहण करने के लिए साधन, विशेषज्ञता, वित्त या यहां तक कि इच्छाशक्ति नहीं है।

ऐसे मामले में, क्या राज्य के लिए यह स्वीकार्य होगा कि वह निजी उद्यम को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे और शहरीकरण के लिए भूमि के विकास और उपयोग के बड़े सार्वजनिक उद्देश्य के लिए

हरियाणा राज्य और अन्य *बनाम*हाकम सिंह और अन्य *
(आर एन ^ मित्तल, जे।

सहायता और सहायता करे? वास्तव में, यह वह भौतिक प्रश्न है जो इस मामले में निर्धारण के लिए आता है।

(सत्रह) ऐसा लगता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार लिया है कि यदि भूमि के अधिग्रहण और बाद में शहरी विकास की प्रक्रिया में, राज्य निजी निगम की सहायता करता है या बाद में इस योजना में लाभ का उद्देश्य है, तो इसे कानून के तहत शक्ति का एक रंगीन प्रयोग माना जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश द्वारा यह देखा गया था:

> उन्होंने कहा, 'मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि अधिसूचनाएं अधिकार क्षेत्र के बेरंग इस्तेमाल से प्रभावित हैं. अधिसूचनाएं जारी करने की आवश्यकता कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुई, जिसे यह भूस्वामियों के साथ बातचीत से प्राप्त नहीं करेगा। कंपनी के पास सेक्टर 10 और 11 में कुछ जमीन थी। याचिकाकर्ता सहित अन्य भूस्वामी भी थे, जिनके पास इन सेक्टरों में जमीन थी। कंपनी भूस्वामियों की भूमि नहीं खरीद सकती थी, बल्कि तथ्य यह प्रतीत होता है कि कंपनी भूमि नहीं खरीदना चाहती थी, हालांकि दिखावा यह था कि भूस्वामियों द्वारा अत्यधिक मूल्य की मांग की जा रही थी, क्योंकि यह सफलतापूर्वक इसे अधिग्रहित करने में कामयाब रही थी। सरकार की एजेंसी का उपयोग करके, कंपनी ने वह हासिल किया जो वह नियंत्रित अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी रूप से हासिल नहीं कर सकती थी।

(अठ्ठारह) तर्क की पूर्वोक्त लकीर और यह आधार मूल रूप से रेखांकित प्रतीत होता है; विद्वान एकल न्यायाधीश का पूरा निर्णय। बड़े सम्मान के साथ, मैं स्पष्ट रूप से एक विपरीत दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक हूं। यह अपरिहार्य और शायद वांछनीय भी प्रतीत होता है कि सभी शहरों में समन्वित शहरीकरण का पूरा भार अपने ऊपर लेने में राज्य की असमर्थता के मामले में, या अन्यथा अच्छे कारणों से, इस निजी उद्यम को न केवल प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, जब तक कि भूमि के शहरी विकास का व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य स्पष्ट और अस्पष्ट न हो। यह उम्मीद करना कि कोई भी निजी संगठन शहरी विकास का भारी बोझ केवल परोपकारी विचारों के लिए उठाएगा और इससे रहित होगा

लाभ या लाभ का कोई भी मकसद बहुत यूटोपियन एक आदर्श होगा। इसलिए, अनिवार्य रूप से, एक बार विनियमित विकास का बड़ा सार्वजनिक उद्देश्य स्पष्ट हो जाने के बाद, लाभ के विचार के लिए भी इस तरह के कार्य को एक निजी निकाय को सौंपना किसी भी तरह से उस बड़े सार्वजनिक उद्देश्य से अलग नहीं होगा या इसे रंगीन नहीं माना जाएगा।

(उन्नीस) न ही मैं इस बात से सहमत हो पा रहा हूं कि कुछ सहायता प्रदान करना, / विनियमित शहरीकरण के उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निजी संगठन को अधिग्रहण (स्पष्ट रूप से बाजार मूल्य पर) शक्ति का एक रंगीन अभ्यास होगा। जैसा कि वर्तमान मामले से पता चलता है, प्रतिवादी-भूमि मालिकों ने निजी बातचीत द्वारा नियोजित शहरी क्षेत्र के केंद्र में अपनी जमीन के टुकड़े को अलग करने से

इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से दिल के सबसे करीब मांस का अपना पाउंड चाहते थे। यदि बढ़ते औद्योगिक शहर फरीदाबाद के समन्वित विकास के हित में, राज्य ने व्यापक जनहित में उनकी संपत्ति के लिए उन्हें बाजार मूल्य का अधिग्रहण करने और भुगतान करने के लिए कदम उठाया है, तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस तरह की कार्रवाई को या तो क्यों खारिज कर दिया जाना चाहिए या रंगीन माना जाना चाहिए।

(बीस) विद्वान एकल न्यायाधीश ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, जब उसे तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जाता है, तो विनियमित शहरी विकास के लिए सभी राज्य या वैधानिक सहायता को खारिज कर दिया जाएगा, जब तक कि यह राज्य द्वारा स्वयं नहीं किया जाता है और वह भी शायद लाभ के उद्देश्य के बिना। यह स्मरण करने योग्य है और शायद इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि कई शहरी क्षेत्रों में राज्य द्वारा विकास स्वयं पूरी तरह से लाभ के तत्व से रहित नहीं है। चंडीगढ़ शहर का हालिया विकास शायद घर के करीब एक प्रमुख उदाहरण है। सम्मान के साथ, मैं महसूस करता हूं कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार को स्वीकार किया जाता है तो यह सरकारी एजेंसियों को छोड़कर सभी शहरी विकास को प्रभावित करेगा और बाद में ऐसा करने में असमर्थ होने की स्थिति में यह कस्बों के आसपास झुग्गियों के अनियंत्रित और अनियमित उदय के राक्षस को बढ़ाएगा जो अंततः एक शहरी परिसर के पूरे विकास को अवरुद्ध कर सकता है।

(इक्कीस) अत, मेरा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्राथमिक रूप से यह कहते हुए गलती की कि चूंकि शहरी विकास का कार्य एक निजी संगठन को सौंपा गया था और राज्य ने उसकी सहायता की थी, इसलिए यह अनिवार्य रूप से शक्ति का एक रंगीन प्रयोग बन जाएगा। इन कुछ अतिरिक्त शब्दों के साथ मैं अपने विद्वान भाई मित्तल, जे की कलम से जो कुछ भी गिरा है, उससे पूरी तरह से सहमत हूं।

एच.एस.बी.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकारी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह इसे अपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा